दिल्ली में आवासीय समस्या

3396. **श्री राम जेठमलानी:** क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली विकास प्राधिकरण की स्थापना दिल्ली की आवासीय समस्या को हल करने के उद्देश्य से की गई थी;

(ख) यदि हां, तो क्या यह भी सच है कि दिल्ली विकास प्राधिकरण आवासीय समस्या को हल नहीं कर पाया है;

(ग) यदि नहीं, तो इस सिलसिले में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(घ) क्या यह भी सच है कि पिछले दशक में इसकी संरचना में सुधार लाने की दृष्टि से कुछ विशेषज्ञ समितियां और आयोग गठित किए गए हैं;

(ङ) यदि हां, तो उनकी कुल संख्या क्या है तथा जिनकी सिफारिशें सरकार ने मार्च 1994 से पहले प्राप्त की हैं, उनकी संख्या क्या है; और

(च) क्या सरकार ने गत कुछ वर्षों के दौरान दिल्ली विकास प्राधिकरण के कार्यकरण में सुधार लाने हेतु कोई कदम उठाए हैं, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी. के. थुंगन): (क) दिल्ली विकास प्राधिकरण का गठन दिल्ली के नियोजित विकास को प्रोत्साहन देने तथा इसे सुनिश्चित करने हेतु किया गया था।

(ख) और (ग) दिल्ली विकास प्राधिकरण ने दिल्ली में आवास समस्या का समाधान करने में उल्लेखनीय योगदान दिया है जैसा कि निम्नलिखित तथ्यों से पता चलता है:

(i) दिल्ली विकास प्राधिकरण ने 1967-68 से लेकर अब तक 17 आवास योजनाएं चलाई हैं जिनके तहत कुल 241810 फ्लैट आवंटित किए गए हैं।

(ii) दिल्ली विकास प्राधिकरण ने रोहिणी पंजीकरण योजना तथा अन्य योजनाओं के माध्यम से सहकारी गृह निर्माण समितियों तथा सहकारी समूह आवास समितियों को प्लाट आवंटित करके 5 लाख से अधिक रिहायशी एककों की व्यवस्था करने में मदद की है।

(iii) झुग्गी-झौंपडी पुनर्वास योजना के माध्यम से 2.5 लाख रिहायशी एकक बनाए गए हैं।

(घ) और (ङ) पिछले दशक के दौरान दिल्ली विकास प्राधिकरण में संरचनात्मक सुधार के प्रयोजनार्थ किसी विशेषज्ञ समिति/समितियों का गठन नहीं किया गया है।

(च) दिल्ली विकास प्राधिकरण के कार्यकरण में और सुधार के निरन्तर प्रयास किये जाते हैं। इस बाबत किये गये कुछ उपाय निम्नलिखित हैं:

(i) विभिन्न स्कीमों के लाभग्राहियों की 18 लोक अदालतों का आयोजन करना;

(ii) गुणवत्ता नियंत्रण उपायों को कड़ा करना;

(iii) बेहतर वित्तीय प्रबन्ध जिसके परिणामस्वरूप गत वर्ष की तुलना में 1993-94 के दौरान दिल्ली विकास प्राधिकरण की आय में 12% वृद्धि हुई;

(iv) भूमि अधिग्रहण में पर्याप्तत: अधिक निवेश;

(v) 1991-92 में 32,921 स्टाफ को घटाकर 1993-94 के अन्त में 27,258 करके लागत प्रभावी प्रबन्ध।

People living in slums

3397. SHRI AHMED MOHMED BHAI PATEL: Will the Minister of URBAN DEVELOPMENT be pleased to state:

(a) how many peoples are living in slums in the major metropolitans at the end of 1990;

(b) how the figures compare with those of 1980 and 1985; and

(c) the details of steps taken by Government to control spreading of slums and to provide basic facilities in the existing slums?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF URBAN DEVELOPMENT (SHRI P.K. THUNGON): (a) The slum population in all the metropolitan cities of the country has been estimated at 20.20 millions in 1991.

(b) The identified slum population of metropolitan cities in 1981 was 14.27 million. There has been about 42% increase in slum population during 1981—1991 in these cities. Slum population of the metropolitan cities for the year 1985 is not available.

(c) The Government has taken various steps both preventive and curative to control spreading of slums as also to provide basic facilities in the existing slums:—